



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

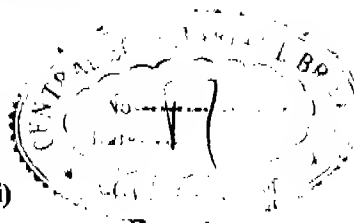
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 104]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 19, 1976/फाल्गुन 29, 1897

No. 104]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 19, 1976/PHALGUNA 29, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## MINISTRY OF INDUSTRY AND CIVIL SUPPLIES

New Delhi, the 19th March 1976

### NOTIFICATION

New Delhi the 19th March 1976

G.S.R. 243(E)/IDRA/30/1/76.—The following draft of rules to amend the Investigation of Industrial Undertakings owned by Companies in Liquidation (Procedure) Rules, 1973, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after sixty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the period so specified will be considered by the Central Government.

### DRAFT RULES

In exercise of the powers conferred by section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes

the following rules to amend the Investigation of Industrial Undertakings owned by Companies in Liquidation (Procedure) Rules, 1973, namely:—

1. These rules may be called the Investigation of Industrial Undertakings Owned by Companies in Liquidation (Procedure) Amendment Rules, 1976.

2. In the Investigation of Industrial Undertakings owned by Companies in Liquidation (Procedure) Rules, 1973, for rules 4, 5 and 6 the following rules shall be substituted, namely:—

4. *Procedure for investigation.*—(1) For the purposes of making an investigation, the investigator shall send a notice to the company concerned, to the registered trade unions, if any, of which the employees of the company are members and to the creditors thereof individually by registered post acknowledgement due.

(2) The investigator shall also publish a notice in regard to the investigation in two successive issues of a leading newspaper published in the English language and of a leading newspaper published in the regional language commonly used in the area in which the company is situated.

(3) The company or any registered trade union or member or creditor thereof may, within a period of twenty one days from the date of received of such notice by the company, trade union, member or creditor, as the case may be, forward its or his suggestions and objections, if any, to the investigator:

Provided that in the event of a company, trade union, member or creditor refusing to accept the notice or sign the acknowledgement, the said period of twenty one days shall be reckoned from the date of such refusal:

Provided further that if the notice is returned on the ground that the company, trade union, member or creditor or any person duly authorised by such company, trade union, member or creditor, as the case may be to receive the notice on its or his behalf is not found, the investigator shall cause the notice to be served on such company, trade union, member or creditor, as the case may be, by affixing a copy of the notice in some conspicuous part of the place where such company, trade union, member or creditor is known to have carried on business or known to have resided or personally worked for gain and the said period of twenty one days shall be reckoned from the date of such affixation.

5. *Opportunity for hearing.*—The investigator shall before the completion of his investigation, give the official Liquidator if any, of the company owing the industrial undertaking or any other person for the time being in charge of the management or control of the industrial undertaking, the employees of the industrial undertaking and the former employees of the industrial undertaking, if any, whose service became discharged by reason of the said company being wound up, a reasonable opportunity of being heard including the opportunity to adduce evidence.

6. *Submission of report.*—(1) The investigator shall, after completing the investigation, submit a report to the Central Government within the period specified in the order appointing such investigator or if no such period is specified therein, within three months from the date on which such order is published in the Official Gazette:

Provided that if the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest so to do, it may extend the period for such period not exceeding one month at a time.

(2) The investigator shall also forward along with his report to the Central Government, the suggestions and objections in original, if any, received from the company, trade union, member or creditor, under rule 4, together with his comments thereon."

[No. 13(5)/Lic. Pol./74.]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

## उद्योग और नागरिक पुति मंत्रालय

### (औद्योगिक विकास विभाग)

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1976

सां. कां. निं. 243 (घ)/आईं. डीं. आरं. एं. 30/1/76.—केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभापनाधीन कम्पनियों के स्वामित्वाधीन औद्योगिक उपक्रमों का अन्वेषण (प्रक्रिया) नियम, 1973 में संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त धारा की उप-धारा (1) में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ दिन के पश्चात् विचार किया जाएगा।

उपर विनिर्दिष्ट अधि से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

#### नियमों का प्रारूप

केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सभापनाधीन कम्पनियों के स्वामित्वाधीन औद्योगिक उपक्रमों का अन्वेषण (प्रक्रिया) नियम, 1973 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम सभापनाधीन कम्पनियों के स्वामित्वाधीन औद्योगिक उपक्रमों का अन्वेषण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1976 है।

2. सभापनाधीन कम्पनियों के स्वामित्वाधीन औद्योगिक उपक्रमों का अन्वेषण (प्रक्रिया) नियम, 1973 में नियम 4, 5 और 6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“4. **अन्वेषण की प्रक्रिया**—(1) अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए अन्वेषक सम्बन्ध कम्पनी को, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों को, यदि कोई हों, जिसके कम्पनी के कर्मचारी सदस्य हैं और उनके नेतृदारों को अलग-अलग रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा एक नोटिस भेजेगा।

(2) अन्वेषक अन्वेषण की बाबत, अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र के दो क्रमवर्ती अकों में और उस क्षेत्रीय भाषा के जो उस क्षेत्र में जिसमें कम्पनी स्थित है उपयोग की जाती है, एक प्रमुख समाचार पत्र में भी नोटिस प्रकाशित कराएगा।

(3) कम्पनी या कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ या उसका कोई सदस्य या नेतृदार, ऐसी नोटिस की प्राप्ति की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर अपने सुझाव या आक्षेप यदि कोई हो, अन्वेषक को प्रस्तुत करेगा।

परन्तु कम्पनी, व्यवसाय संघ, सदस्य या लेनदार द्वारा नोटिस लेने से या अभिस्वीकृति पर हस्ताक्षर करने से इनकार करने की दशा में इक्कीस दिनों की उक्त अवधि की गणना से इनकार करने की तारीख से की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि नोटिस इस आधार पर वापस कर दी जाती है कि कम्पनी, व्यवसाय संघ, सदस्य या लेनदार या यथास्थिति ऐसी कम्पनी व्यवसाय संघ, सदस्य या लेनदार द्वारा उसकी ओर से नोटिस प्राप्त करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है तो अन्वेषक यथास्थिति, ऐसी कम्पनी, व्यवसाय संघ, सदस्य या लेनदार पर नोटिस की तामील, उस स्थान के सहजदृश्य भाग पर नोटिस की एक प्रति चिपका कर करेगा, जहां यह ज्ञात है कि ऐसी कम्पनी, व्यवसाय संघ, सदस्य या लेनदार कारबार करता था या कर रहा था या लाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से काम किया है और इक्कीस दिन की उक्त अवधि की गणना नोटिस के इस प्रकार चिपकाए जाने की तारीख से की जाएगी ।

5. **सुनवाई का अवसर**—अन्वेषक, अपना अन्वेषण पूर्ण करने के पहले ऐसे औद्योगिक उपक्रम के स्वामित्व वाली कम्पनी के शासकीय समापक, यदि कोई हो, या उस समय औद्योगिक उपक्रम के प्रबन्ध या नियंत्रण के भारसाधक किसी अन्य व्यक्ति को तथा औद्योगिक उपक्रमों के कमचारी या भूतपूर्व कर्मचारी को यदि कोई हो, जिनकी उक्त कम्पनी के सभापन के कारण सेवाएं समाप्त हो गई थी, सुनवाई का व्यक्ति युक्त अवसर देगा जिसमें साक्ष्य पेश करने का अवसर सम्मिलित है ।

6. **रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण**—(1) अन्वेषक, अन्वेषण पूर्ण करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे अन्वेषक नियुक्त करने के आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या यदि उस में कोई अवधि विनिर्दिष्ट न हो ऐसे आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के तीन मास के भीतर, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय में लोक हित में ऐसा करना समीचीन है तो वह उस अवधि को एक मास से अनधिक की अवधि तक बढ़ा सकेगी ।

(2) अन्वेषक अपनी रिपोर्ट के साथ-साथ ऐसे कम्पनी, व्यवसाय संघ, सदस्य या लेनदार से नियम 4 के अधीन प्राप्त सुझावों और आक्षेपों को अपने टिप्पणों सहित, केन्द्रीय सरकार को मूल रूप में भेजेगा ।

[सं० 13(5) ता० ५०/74]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।